अनुसूचित जातियों के बेरोजगार पायलट

196. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **पर्यटन और** नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में ग्रेड एक, दो और तीन के पदों में अब तक आरक्षित कोटे के अनुसार अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती नहीं की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक हरिजन/अनुसूचित जाति के पायलट, जिनके प्रशिक्षण पर सरकार ने भारी व्यय किया है, अभी भी बेरोजगार हैं ; और

(ग) इन मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे. बी. पटनायक) : (क) जी, नहीं। एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइस दोनों ही ने ग्रेड I, II तथा III में, इन वर्गों की रिक्तियों के आरक्षण संबंधित सरकारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की, जहां तक उपयुक्त एवं योग्य व्यक्ति उपलब्ध हो सके हैं, भर्ती की है।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुछ ऐसे बेरोजगार विमानचालक हैं जिन्हे इंडियन एयरलाइंस द्वारा चयन के समय एक मौका दिया गया था परन्तु वे उपयुक्त नहीं पाये गये, वस्तुतः नियमित भर्ती के अलावा, इंडियन एयरलाइंस ने 1977 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये एक अलग से भी चयन किया था और जो उम्मीदवार उपयुक्त पाये गये, उन्हें शिक्षण पर ले लिया गया था। इंडियन एयरलाइंस तथा सरकार का यह सतत प्रयत्न रहता है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाये कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों को इन वर्गों के ही उपयुक्त उम्मीदवारों द्वारा भरा जाये।

दिल्ली में सस्ते होटल तथा पर्यटक दुकानें

197. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **पर्यटन तथा नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पर्यटन विभाग द्वारा बड़े होटलों के बजाय दिल्ली में तथा देश के अन्य स्थानों पर छोटे तथा सस्ते होटल तथा पर्यटक दुकाने खोलने की कोई योजना बनाई जा रही है ?

पर्यटन तथा नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) जी, हां। अधिक लागत वाले, मंहगे होटलों के बजाय, जिनके लिये कि अधिक परिव्यय की आवश्यकता होती है, पर्यटन योजना में उपलब्ध सीमित संसाधनों के अन्तर्गत कम लागत वाले, सस्ते होटल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसरण में और साथ ही स्वदेशी पर्यटकों और अन्तर्राष्ट्रीय मितव्ययी पर्यटकों की स्वच्छ, आरामदेह और सस्ते आवास की जरूरत को पूरा करने के लिये नई दिल्ली में एक 1250 बैड वाले जनता होटल (अशोक यात्री निवास) का निर्माण किया जा रहा है। पंचवर्षीय योजना 1978–83 के अन्तर्गत बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के महानगरों में इसी प्रकार की यूनिटों का निर्माण करने का कार्यक्रम है। अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों पर, जिनका निर्धारण एक सर्वेक्षण कराने के उपरान्त किया जायेगा, अपेक्षाकृत छोटे-छोटे यूनिटों की स्थापना की जायेगी, बशर्ते निधियां उपलब्ध हों। राज्य सरकारों और गैर-सरकारी उद्यमियों को कम कीमत वाले होटलों की स्थापना करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। इस उद्देश्य के लिये उनके अनुरोध पर उन्हें डिजाइन भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

198. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन को दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने में पूरी सफलता नहीं मिल पाई ;

(ख) क्या प्रशासन द्वारा बार-बार घोषनायें किये जाने के बावजूद उचित दर की दुकानों के माध्यम से साबुन का वितरण बिल्कुल नहीं हुआ और कपड़े तथा कापियों का वितरण भी नगण्य ही रहा है ; और

(ग) दिल्ली में सार्वजनिक प्रणाली में व्यापक सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और इस्पात तथा खान मंत्री (श्री प्रचय मुखर्जी) (क) से (ग) : दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में इस समय कुल 2,160 उचित दर की दुकाने हैं। उचित दर की दुकानों के माध्यम से लगभग 11 लाख खाद्य कार्डधारकों को गेहूं, चावल, चीनी, आटा, आर० बी० डी० ताड़ का तेल, रेपसीड तेल और कापियों जैसी कुछ चुनी आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। उचित दर की दुकानों के अलावा, 1148 खुदरा डिपुओं के माध्यम से मिट्टी के तेल और 1638 डिपुओं के जरिये कोयले का वितरण किया जा रहा है। 800 रु० प्रतिमाह से कम मासिक आय वाले खाद्य कार्डधारियों को 244 सहकारी समितियों के माध्यम से कंट्रोल के कपड़े का वितरण किया जा रहा है। यद्यपि, कापियों और कंट्रोल